Raj Express (Indore), 06th November 2024, Page-12

मुख्यमंत्री ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

आईआईटी की तर्ज पर विकसित करें सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज

सीएम डॉ. यादव ने कहा- पीपीपी मोड पर बनाएं आईटी पार्क

भोपाल, प्रसं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि शासकीय विभाग जन-कल्याण के लिए ड्रोन तकनीक के अधिक उपयोग के लिए प्रयास बढ़ाएं। अवैध वृक्ष कटाई, अवैध खनिज उत्खनन, सघन बस्तियों में पुलिस पेट्रोलिंग में ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाया जाए।

वन क्षेत्रों में शिकार की घटनाएं भी ड्रोन तकनीक से ज्ञात कर अपराधियों को दंडित करने में उपयोग किया जाए। मैपकास्ट के साथ क्रिस्प और इस तरह की अन्य संस्थाएं समान स्वरूप की गतिविधियों का संयुक्त रूप से समन्वय पूर्वक संचालन करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 6 पुराने शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों को आईआईटी की तर्ज पर विकसित किया जाए। आवश्यकता अनुसार इंडस्ट्री की मदद कॉलेज को विकसित करने में ली जाए। मुख्यमंत्री मंगलवार को मंत्रालय में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पीपीपी मोड से आईटी पार्क बनाए जाएं। इंदौर, उज्जैन और रीवा में इन संभावनाओं को साकार किया जाए। सभी आईटी प्रोजेक्ट्स के कार्यों की समय-सीमा तय कर कार्य करें।

जितने पुलिसकर्मी सेवानिवृत्त हो रहे, हर साल उतनी भर्ती सुनिश्चित करें

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि जिस अनुपात में पुलिसकर्मी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उस अनुपात में हर साल भर्ती की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात में यदि अधिक पुलिस बल की जरूरत हो, तो तदानुसार भर्ती की जाए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आगामी वर्षों में पुलिसकर्मी और विभिन्न पदक्रमों पर पर्याप्त बल उपलब्ध हो और प्रदेश में काडर मैनेजमेंट व्यवस्थित बना रहे। सीएम ने एडीजी स्तर के अधिकारियों को नियमित रूप से संभाग स्तर पर दौरे और अपराधों की समीक्षा करने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के दुरुपयोग और साइबर क्राइम के खतरे से समाज को बचाने के लिए मप्र पुलिस को फ्यूचर रेडी होना होगा। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी की अद्यतन तकनीकों का उपयोग करते हुए प्रत्येक थाने में साइबर डेस्क, हर जिले में सायबर थाना और राज्य स्तर पर कॉल सेंटर स्थापित किया जाए। साग़र फ्रॉड और क्राइम से लोगों को बचाने सघन जागरूकता अभियान चलाया जाए। नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सघन मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही गौ-तस्करों पर भी कठोर कार्रवाई की जाए।

नक्सल गतिविधियों को समाप्त करने सघन ऑपरेशन चलाएं-मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च, 2026 तक नक्सल गतिविधियों को पूर्णतः समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश के संभावित नक्सल क्षेत्र में सघन ऑपरेशन चलाया जाए। इसके लिए निश्चित समय सीमा में आवश्यकतानुसार हॉक-फोर्स की भर्ती की जाए।

एमपीएसईडीसी को देंगे सिंहस्थ-2028 का जिम्मा

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों में मप्र राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड (एमपीएसईडीसी) के माध्यम से साइबर सुरक्षा के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ-2028 के लिए भी नगरीय प्रशासन विभाग के आईटी प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी एमपीएसईडीसी को दी जाएगी। इसके लिए एमपीएसईडीसी द्वारा अभी से प्लान बनाकर कार्य किया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि उद्योगों के लिए सभी विभागों का इंटीग्रेटेड सिंगल विंडो सिस्टम डेवलप किया जाए।

भोपाल में होगी राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस

मप्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक अनिल कोठारी ने बताया कि भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का भोपाल में 3 से 6 जनवरी, 2025 तक आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के 1200 विद्यार्थी, विषय विशेषज्ञ और वैज्ञानिक शामिल होंगे। मप्र कारीगर विज्ञान सम्मेलन फरवरी में होगा।

10 औद्योगिक इकाइयों के प्रकरण मंजूर 2100 करोड़ रुपए का निवेश आएगा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति की बैठक में मेगा स्तर की औद्योगिक इकाइयों के 10 प्रकरणों को कस्टमाइज्ड पैकेज के रूप में स्वीकृति दी गई। इन परियोजनाओं में लगभग 2100 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की संभावना है। प्रस्तावित परियोजनाओं से करीब 6200 व्यक्तियों को सीधे रोजगार प्राप्त होने का अनुमान है। बैठक में टेक्सटाइल की 3 इकाइयों व खाद्य प्रसंस्करण की 5 इकाइयों से संबंधित प्रकरणों पर विचार किया गया।